'नेशन विद नमो' के जरिए युवा, महिलाओं व दलित को साधेगी भाजपा

पांच राज्यों में हार के बाद भाजपा की नई रणनीति : 'पहला वोट मोदी के नाम' से जोड़ेगी पहली बार वोट देने वाले युवा

नई दिल्ली। हिन्दी पट्टी के तीन राज्यों में पराजय के बाद, अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में 2014 जैसे नतीजे दोहराने के लिए प्रयासरत भाजपा 'नेशन विद नमो' और 'पहला वोट मोदी के नाम' अभियान के जरिये युवाओं एवं पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को साधेगी। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने एजेंसी को बताया कि भाजपा का मंत्र सबका साथ, सबका विकास है। आगामी लोकसभा चुनाव में हमारा जोर युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों, सैनिकों पर रहेगा। पार्टी का, अपनी चुनावी रणनीति के तहत किसानों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में किसान कुंभ, बिरसा ग्राम सभा, भीम समरसता भोज, उज्ज्वला रसोई कार्यक्रम आयोजित करने का वृहद कार्यक्रम है। पार्टी 12 जनवरी को 'नेशन विद नमो' अभियान को औपचारिक रूप से आगे बढ़ायेगी। इसके तहत आने वाले समय में 'नेशन विद नमो वॉलन्टियर' के जरिये देश में 50 लाख युवाओं को संकल्प दिलाया जायेगा। साथ ही पार्टी 15 जनवरी से 10 फरवरी तक देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में युवा संसद कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए 'पहला वोट मोदी के नाम' पहल शुरू की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में 2000 में जन्म लेने वाले और 2019 के चुनाव में पात्र मतदाताओं का उल्लेख किया था। तब से ही भाजपा इस पहल को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भाजपा को शिकस्त मिली है, जहां लोकसभा की 65 सीटें हैं। भाजपा ने 2014 के चुनाव में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर 2019 में यह संख्या घटकर आधी रह सकती है। ऐसे में पार्टी इस हार से उबरकर लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने में जुटी है।

हिंदी पट्टी में हुए नुकसान की भरपाई पार्टी दक्षिण, पूर्व एवं पूर्वोत्तर राज्यों से करने की तैयारी में है। इस मकसद से प्रधानमंत्री मोदी केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में दो दर्जन से ज्यादा रैलियां करेंगे। इन इलाकों से लोकसभा की 122 सीटें आती हैं। भाजपा पदाधिकारी ने बताया कि आने वाले चुनाव में किसान एवं कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। ऐसे में किसान परिवारों तक इसके व्यापक प्रचार के लिये देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। किसान को जोड़ने की पहल के तहत तीन स्तर पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय और प्रदेश टीम के साथ जिला प्रभारियों को इस कार्य में लगाया गया है। साथ ही तहत पंचायत स्तर पर 'किसान कुंभ ग्राम सभा' का आयोजन भी होगा। पार्टी ने हर बूथ पर लगभग दो दर्जन कार्यकर्ताओं की टोली बनाई है। यह टोली प्रति दिन सुबह-शाम और छुट्टी वाले दिनों में घर-घर जाकर परिवारों से मिलेगी तथा दुकानदारों एवं अन्य छोटे-मोटे काम करने वालों से भी संपर्क करेगी।

'एक्सीडेंटल पीएम' का प्रचार भाजपाई स्टंट : अमरिंदर

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा 'द ऐक्सीडेंटल प्राइममिनिस्टर' फिल्म का प्रचार पार्टी का 'महज राजनीतिक स्टंट' तथा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कमतर पेश करने की 'बदहवास' कोशिश है।

कई विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने इस फिल्म का ट्रेलर ट्वीट करने पर पिछले हफ्ते भाजपा की निंदा की है। यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारु की पुस्तक पर आधारित एक राजनीतिक ड्रामा है। फिल्म में अनुपम खेर मनमोहन सिंह और अक्षय खन्ना संजय बारु के किरदार में हैं। उसके ट्रेलर में सिंह को 2014 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरुनी राजनीति के शिकार के तौर पर दिखाया गया है। अमरिंदर सिंह ने एक बयान में कहा कि मनमोहन सिंह को 'कमजोर और दब्बू' प्रधानमंत्री के रुप में पेश करने की भाजपा की कोशिश 'न केवल बचकाना बल्कि राजनीति से प्रेरित है।'

अन्य खबरें

अवैध रूप से बसे छह बांग्लादेशियों को चार साल की कैद

ठाणे (महाराष्ट्र)। अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने के दोषी छह बांग्लादेशियों को चार साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनएच मखरे ने पिछले सप्ताह दिए अपने आदेश में प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर एटीएस ठाणे ने मार्च, 2018 में भिवंडी कस्बे के एक आवासीय भवन पर छापेमारी कर छह बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, जो वैध दस्तावेजों/पासपोर्ट के बगैर रह रहे थे।

गणतंत्र दिवस पर द. अफ्रीका के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि

नई दिल्ली। देश के गणतंत्र दिवस पर इस बार मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं और इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है क्योंकि पूज्य बापू व दक्षिण अफ्रीका का एक अटूट सम्बन्ध है।

इंडोनेशिया में फिर ज्वालामुखी में विस्फोट

देनपसार। इंडोनेशिया के पर्यटक स्थल बाली में एक ज्वालामुखी में ताजा विस्फोट से आसमान में गरम राख फैल गई है। ज्वालामुखी विज्ञान और भूगर्भ एजेंसी ने कहा कि रविवार को ज्वालामुखी 'माउंट अगुंग' करीब तीन मिनट तक फटता रहा, जिसकी वजह से आसमान में सफेद धुंआ और 700 मीटर ऊंची राख फैल गई। हालांकि विस्फोट के चलते कोई नुकसान नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों ने पर्यटकों को ज्वालामुखी के चार किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र से दूर रहने को कहा है।

भ्रष्टाचार में दोषी ठहराने के फैसले को चुनौती देंगे शरीफ

लाहौर। पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अल - अजीजिया स्टील मिल मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने को इस हफ्ते इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। पीएमएल - एन प्रमुख को भ्रष्टाचार को लेकर सात साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनके वकील ने यह जानकारी दी। पिछले सोमवार को इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार रोधी एक अदालत ने 68 वर्षीय शरीफ को अल - अजीजिया स्टील मिल मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई थी।

ओबीसी जातीय सर्वेक्षण की जरूरत

उपवर्गीकरण का अध्ययन कर रहे आयोग ने मंत्रालय को लिखा पत्र

अमर भारती संवाददाता

- ओबीसी आरक्षण के समान बंटवारे के लिए मानदंड बनाने के लिए जरूरी
- समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी रोहिणी ने लिया निर्णय

नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची के उपवर्गीकरण का अध्ययन कर रहे एक आयोग ने एक एजेंसी से देशव्यापी सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है ताकि जातिवार आबादी के आंकड़े जुटाए जा सकें और उसने इसके लिए केंद्र से निधि भी मांगी है।

पांच सदस्यीय समिति का नेतृत्व कर रही न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जी रोहिणी ने इस संबंध में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को पत्र लिखा है। इस समिति का गठन ओबीसी आरक्षण के समान बंटवारे के लिए मानदंड तय करने का सुझाव देने के लिये किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर को आयोग का कार्यकाल 31 मई 2019 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी। न्यायाधीश रोहिणी के अनुसार, ओबीसी की केंद्रीय सूची में 2,600 से अधिक जातियां हैं जिनमें से कई की संख्या छोटी है और भौगोलिक रूप से अलग स्थानों पर रहती है इसलिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर उप जिले को शामिल करते हुए व्यापक नमूने की आवश्यकता है। उन्होंने मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि ओबीसी की केंद्रीय सूची के उपवर्गीकरण के उद्देश्य के लिए हमारे आयोग को जातिवार आबादी के आंकड़ों के आकलन की जरुरत है।

उन्होंने कहा कि चूंकि आजादी के बाद जातिवार आबादी के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं इसलिए आयोग ने सक्षम सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर एक सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है।

न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जी रोहिणी ने कहा कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल विभिन्न जातियों और समुदायों की आबादी का पता करने के अलावा यह सर्वेक्षण ओबीसी परिवारों में शिक्षा का स्तर और रोजगार की स्थिति के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएगा। सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार से निधि की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के लिए 200 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट की जरुरत होगी।

कंप्यूटर निगरानी एजेंसियों को पूर्ण शक्तियां नहीं, लेनी होगी हर बार मंजूरी

अमर भारती संवाददाता

- गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी जानकारी
- संप्रग सरकार में बना था कम्प्यूटर डेटा निगरानी नियम

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि केन्द्र सरकार ने किसी कम्प्यूटर से जानकारी निकालने (इंटरसेप्ट) के लिए किसी भी एजेंसी को 'पूर्ण शक्ति' नहीं दी है। इन एजेंसियों को इस तरह की कार्रवाई के दौरान वर्तमान नियम कानून का कड़ाई से पालन करना होगा। अधिकारी ने कहा कि कोई नया कानून, कोई नया नियम, कोई नई प्रक्रिया, कोई नई एजेंसी, कोई पूर्ण शक्ति, कोई पूर्ण अधिकार जैसा कुछ नहीं है और यह पुराना कानून, पुराना नियम, पुरानी प्रक्रिया और पुरानी एजेंसियां हैं। अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर एजेंसी को बताया कि 'वर्तमान नियम शब्दशः वही है और इस में कौमा या फुल स्टॉप का भी कोई फर्क नहीं है।' गृह मंत्रालय की 20 दिसंबर की अधिसूचना में 10 एजेंसियों का नाम लिया गया था। इस अधिसूचना ने राजनीतिक भूचाल ला दिया था और विपक्ष ने सरकार पर 'निगरानी राज्य' बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना में बताई गई दस एजेंसियों को 2011 से इलेक्ट्रोनिक संचारों को बीच में रोककर जानकारी हासिल की शक्ति पहले से थी।

गृह मंत्रालय ने इस साल 20 दिसंबर को इन एजेंसियों का उल्लेख करते हुए 2011 की 'आदर्श परिचालन प्रक्रियाओं' को दोहराया था जिसमें कहा गया कि इस तरह के हर 'इंटरसेप्ट' के लिए संबंधित प्राधिकार (केन्द्रीय गृह सचिव या राज्य गृह सचिव) से पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी। केन्द्र सरकार का कहना है कि कम्प्यूटर डेटा को हासिल करके जानकारी लेने और इसकी निगरानी करने के नियम 2009 में उस समय बनाए गए थे जब कांग्रेस नीत संप्रग सत्ता में थी और उसके नये आदेश में केवल उन एजेंसियों का नाम बताया है जो इस तरह का कदम उठा सकती हैं।

बालगृहों के कर्मियों का पुलिस सत्यापन कराएं राज्य सरकारें

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों के बालगृहों में हुई यौनशोषण की कथित घटनाओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने यहां चल रहे सभी बालगृहों के कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराएं ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिवों के नाम लिखे पत्र में कहा है कि बालगृहों के सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराएं, आगे नयी नियुक्तियों से पहले भी पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करें तथा 30 जनवरी, 2019 तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपे। कानूनगो ने समाचार एजेंसी को बताया कि किशोर न्याय कानून-2015 और 2016 में लागू किशोर न्याय नियमों के तहत यह अनिवार्य है कि पुलिस सत्यापन के बिना बालगृह में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती।

कामकाज बंदी के लिए डेमोक्रैट्स जिम्मेदार : ट्रंप

वाशिंगटन। सप्ताह भर से आंशिक रूप से ठप पड़े सरकारी कामकाज को फिर से पटरी पर लाने के लिए हो रही बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार डेमोक्रैट्स को निशाना बनाकर ट्वीट कर रहे हैं। ट्रंप क्रिसमस के दौरान फ्लोरिडा के क्लब में छुट्टियां मनाने के बजाए इस ठप पड़े कामकाज को लेकर व्हाइट हाउस में फंसे हुए हैं। संघीय सेवाओं और सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की समस्या नये साल में भी जारी रहने की आशंका है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के दौरान समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ भी नहीं दिख रहा है।

बांग्लादेश में मतदान के दौरान हिंसा में 11 की मौत

एजेंसी

अधिकांश स्थानों में अवामी लीग के समर्थकों और विपक्षियों में हुई झड़पें मृतकों में एक सुरक्षा कर्मी भी

ढाका। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार की सुबह मतदान शुरू होने के बाद हुई चुनावी हिंसा में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। सत्तारूढ़ अवामी लीग और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोनों ही एक-दूसरे के समर्थकों और उम्मीदवारों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। देश में पहली बार आम चुनाव के लिए कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल हुआ। कुल 299 संसदीय क्षेत्रों में से केवल छह क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया।

सुबह आठ बजे मतदान शुरू होने के बाद राजधानी में ढाका सिटी सेन्टर कॉलेज में सबसे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वोट डाला। हसीना के रिश्तेदार एवं पार्टी सांसद फजले नूर तापस इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के बाद हसीना ने कहा कि मुझे अपने लोगों पर यकीन है कि वे हमें चुनेंगे। एक ओर जहां हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर जेल में बंद उनकी चिर प्रतिद्वंदी खालिदा जिया का भविष्य अधर में लटका नजर आता है। इस बीच, देश में विभिन्न जगहों पर हुई चुनावी हिंसा में कम से कम 10 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। मीडिया में हालांकि 11 लोगों के मरने की खबर है। चुनावी हिंसा में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। एक खबर के अनुसार, देश में रंगमती के कावखाली में सत्तारूढ़ अवामी लीग और विपक्षी बीएनपी समर्थकों के बीच झड़प में जुबो लीग के एक नेता की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। चटगांव में बीएनपी का कार्यकर्ता मारा गया जबकि राजशाही में अवामी लीग के समर्थक की मौत हुई है। नरसिंहगड़ी-3 संसदीय क्षेत्र में आवामी लीग का एक पोलिंग एजेंट मारा गया है। राजशाही-3 के मोहनपुर में बीएनपी के कार्यकर्ता ने हमला कर आवामी लीग के समर्थक की हत्या कर दी। वहीं चांडिना में पुलिस की गोलीबारी में ओकियाफ्रंट का एक समर्थक मारा गया है। दिनाजपुर-2 में एक, कॉक्स बाजार-1 में एक, बोगुरा-4 में बगैल एक, नोवाखाली-3 में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई।

जयललिता की मौत के लिए स्वास्थ्य सचिव पर साजिश का लगाया आरोप

एजेंसी

जांच कर रहे आयोग के वकील ने याचिका की दायर

चेन्नई। पूर्व मुख्मयंत्री जे जयललिता की मौत की जांच कर रहे जांच आयोग के वकील ने एक याचिका में आरोप लगाया है कि तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने अपोलो अस्पताल के साथ साठगांठ और साजिश की तथा उनका 'अनुपयुक्त उपचार' किया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार आयोग के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि 2016 में जयललिता को अस्पताल में भर्ती किये जाने के समय तत्कालीन मुख्य सचिव पी राम मोहन राव ने 'जानबझकर झूठे सबूत दिए'। इन अरोपों का स्वास्थ्य सचिव और अस्पताल दोनों ने जोरदार खंडन किया है जबकि पूर्व मुख्य सचिव ने कहा कि उन्हें याचिका की जानकारी नहीं है। न्यायमूर्ति ए अरुमुगस्वामी आयोग के स्थायी वकील मोहम्मद जाफरुल्लाह खान ने पैनल के समक्ष दायर याचिका में राधाकृष्णन और राव पर प्रतिवादी के तौर पर मुकदमा चलाने की मांग की है। वकील की याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य सचिव ने पैनल के सामने विरोधाभासी बयान दिये और वह जयललिता को इलाज के वास्ते विदेश ले जाने के भी विरुद्ध थे। याचिका में कहा गया है, 'अतएव, यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सचिव की गवाही न केवल विरोधाभासी है बल्कि वह दिवंगत मुख्यमंत्री के अनुपयुक्त उपचार के संबंध में स्वास्थ्य सचिव और अपोलो अस्पताल के बीच साठगांठ का भी संकेत करती है।

अफगनिस्तान में 19 आतंकवादी ढ़ेर

काबुल। अफगानिस्तानी वायु सेना ने फरयाब प्रांत में स्थित कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया तथा 19 आतंकवादियों को मार गिराया जबकि सात अन्य घायल हो गये। आतंकवादियों के हमले में बच्चा समेत चार नागरिकों की मौत हो गयी।

प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता अब्दुल कीरम युरुस ने रविवार को बताया कि ये हवाई हमले शनिवार को देर शाम को किये गये थे। ये हमले अशांत एवं उपद्रवग्रस्त ख्वाजा सब्ज पोश और कायसार जिलों में किये गये थे। इस दौरान तीन स्थानीय नेताओं मुल्लाह अहमद, कारी फीदा मोहम्मद और मुल्लाह खैरुल्लाह समेत 19 आतंकवादी मारे गये तथा सात अन्य घायल हो गये। मारे गये आतंकवादियों में तीन विदेशी हैं।

रेलवे की फ्रंट कोरीडोर परियोजना के प्रशिक्षण को दौड़ी मालवाहन गाड़ी

एजेंसी

अजमेर। बहुउपयोगीय रेलवे फ्रंट कोरीडोर परियोजना के तहत आज अजमेर मंडल के मदार रेलवे स्टेशन से रेवाड़ी तक की 306 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रंट कोरीडोर कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसी) ट्रैक के प्रशिक्षण के तहत पहली माल वाहन गाड़ी का आज शुभारंभ किया गया।

यह गाड़ी अजमेर के मदार स्टेशन से रेवाड़ी तक जाएगी। इस बीच जयपुर मंडल के किशनगढ़ से सत्रह किलोमीटर दूर फुलेरा के नजदीक बनाए गए न्यू साखुन पर नई रेलवे स्टेशन भवन का भी शुभारंभ किया गया। डीएफसीसी के प्रबंध निदेशक अनुराग सचान एवं जयपुर रेल मंडल प्रबंधक सौम्या माथुर ने संयुक्त रूप से साखुन स्टेशन से माल वाहन रेलगाड़ी को रेवाड़ी के लिए रवाना किया। यह रेलगाड़ी 46 कंटेनर लेकर करीब सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और न्यू रेवाड़ी तक जाएगी। सचान ने माल वाहन गाड़ी को रवाना करने के बाद पत्रकारों को बताया कि पूरे देश के लिए गोल्डन कोर्डिनेटर के तहत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई को केंद्र मानते हुए सवारी गाड़ियों के ट्रैक को खाली कर नये ट्रैक को माल वाहन गाड़ियों के लिए बिछाया गया है जो कि अप लाइन-डाउन लाइन के जरिए पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से संचालित होगी। जब इस दौर का काम पूरा हो जाएगा तो 120 गाड़ी का प्रतिदिन आवागमन होगा जो पूरे देश के लिए माल परिवहन का काम करेंगी जिससे भारतीय रेल को तो फायदा होगा ही साथ ही राजस्थान के सीमेंट उद्योग को बड़ी मात्रा में फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का पहला चरण दिल्ली से फुलेरा, द्वितीय चरण आज मदार स्टेशन तक तथा तीसरा चरण मदार से मारवाड़ जंक्शन तक तैयार किया जाएगा जो आगामी मार्च तक पूरा कराया जाने का लक्ष्य है। साथ ही मारवाड़ से गुजरात के पालनपुर तक ट्रैक निर्माण का कार्य अगले वर्ष सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मार्च 2020 तक संपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद माल परिवहन का एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा।

सभी को घर मुहैया कराने में सरकार 12 फीसदी सफल

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। सरकार शहरी क्षेत्रों में 2022 तक सभी जरूरतमंदों को आवास सुविधा मुहैया कराने के लिये एक करोड़ सस्ते आवास बनाने की मंजिल तक पहुंचने का अब तक 12 फीसदी सफर तय कर पाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सस्ते आवास बनाने की योजना को अंजाम दे रहे केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय को योजना की गति बढ़ाने के लिये अब त्वरित भवन निर्माण संबंधी 24 नयी तकनीकों का सहारा है।

आवास के अलावा सौ स्मार्ट शहर बनाने की योजना को आगे बढ़ा रहे मंत्रालय के पास 2018 खत्म होने तक एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसे स्मार्ट सिटी परियोजना के मानकों पर शत प्रतिशत खरा माना जा सके। हालांकि मंत्रालय की दलील है कि स्मार्ट सिटी परियोजना में शहरों के स्वरूप का बदलाव चरणबद्ध तरीके से दिखना शुरु होगा। आवास योजना के बारे में मंत्रालय का दावा है कि जून 2015 में शुरु हुयी इस योजना के तहत 2018-19 में आवास निर्माण की गति सबसे ज्यादा रही। मंत्रालय के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में 35.67 लाख घर निर्माणाधीन हैं। जबकि 12.45 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

आरबीआई ने नेत्रहीनों को नोट पहचानने में मदद के लिए सहूलियत देने की तैयारी की दी शुरू

मोबाइल से नोट की पहचान कर सकेंगे नेत्रहीन

- देश में हैं करीब 80 लाख नेत्रहीन या दृष्टिबाधित लोग
- पूरी तरह से सॉफ्टवेयर आधारित हो सकता है समाधान

अमर भारती संवाददाता

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नेत्रहीनों को नोटों की पहचान करने में सहूलियत देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिये आरबीआई मोबाइल फोन आधारित समाधान खोज रहा है। वर्तमान में, नेत्रहीनों को नोट पहचानने के लिये 100 रुपये और उससे ऊपर के नोटों की छपाई इस रूप से उभरते रूप (इंटैग्लियो प्रिंटिंग) में होती है जिससे वे स्पर्श कर उसे पहचान सके। देश में करीब 80 लाख नेत्रहीन या दृष्टिबाधित लोग हैं, जिन्हें केंद्रीय बैंक की नई पहल से फायदा मिल सकता है।

आरबीआई ने जून 2018 में घोषणा की थी कि वह नेत्रहीनों द्वारा मुद्रा की पहचान करने में मदद करने के लिये उचित उपकरण या तंत्र की व्यवहार्यता का पता लगायेगा। इसी तर्ज पर अब आरबीआई ने भारतीय मुद्रा के मूल्यवर्ग की पहचान के लिये तंत्र/उपकरण विकसित करने के लिये वेंडरों से रुचि पत्र मंगाये हैं। निविदा दस्तावेज में कहा गया है कि हाथ से चलने वाला यह उपकरण/तंत्र नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में सक्षम होना चाहिये। जब भी बैंक नोट को इसके सामने/पास/इसके अंदर या उससे होकर गुजारा जाये तो कुछ ही सेकंड (दो सेकंड या उससे भी कम समय में हिंदी/अंग्रेजी में मूल्यवर्ग की जानकारी मिलनी चाहिये अर्थात् यह पता चलना चाहिये कि नोट कितने का है। समाधान पूरी तरह से सॉफ्टवेयर आधारित हो सकता है जो मोबाइल फोन या हार्डवेयर की मदद से या दोनों के संयोजन से चलने में सक्षम हो।यदि समाधान हार्डवेयर आधारित समाधान हो तो बैटरी से चलने वाला, रिचार्ज हो जाने वाला, छोटा और पकड़ने में आरामदायक हो। साथ ही उसे अतिरिक्त रोशनी की जरुरत नहीं होनी चाहिये।

नरेंद्र मोदी ब्लैकमेलर हैं : चंद्रबाबू नायडू

अमरावती। हफ्ते भर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दूसरी बार हमला करते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को उन्हें 'ब्लैकमेलर' करार दिया, जो अपनी बात मनवाने के लिए हर किसी को 'धमकी' देते हैं।

गौरतलब है कि पिछले रविवार को नायडू ने प्रधानमंत्री को 'खोखला व्यक्ति' बताया था, जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पर आंध्रप्रदेश की वृद्धि बाधित करने के उद्देश्य से इस राज्य के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मोदी ब्लैकमेलर हैं। वह मामले बनाते हैं और फिर उसे ब्लैकमेल करते हैं।

अमर भारती मे प्रकाशित समाचार, विचार, लेख अथवा विज्ञापन से यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो कृपया स्पष्टीकरण एवं सुझाव समूह सम्पादक की ईमेल- editor@amarbharti.com पर प्रेषित करे अथवा 9311222595 पर व्हाट्सएप्प करें।